



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 2005/माघ 18, 1926

No. 38]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 2005/MAGHA 18, 1926

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2005

विषय : चीन जन. गण. तथा स्वीडन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेंटेरीथ्रिटोल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच शुरू करना।

सं० 14/16/2004- डीजीएडी : में० कनोरिया कोनेकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन, संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है जिसमें चीन जन. गण. तथा स्वीडन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेंटेरीथ्रिटोल के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जाँच शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

1. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान मामले में शामिल उत्पाद पेंटेरीथ्रिटोल, एक कार्बनिक यौगिक (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) है। संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क उपशीर्ष 29.05.42 तथा सुमेलीकृत प्रणाली पर आधारित भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत है। जिस वर्गीकरण के तहत संबद्ध वस्तु का आयात किया जा रहा है उस पर विचार किए बिना विचाराधीन वस्तु के संबंध में जाँच प्रारंभ की जा रही है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि पेंटेरीथ्रिटोल तकनीकी अथवा नाइट्रेशन ग्रेड का हो सकता है। दोनों ग्रेडों को विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित जाँच के क्षेत्र के भीतर शामिल किया गया है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि पेंटेरीथ्रिटोल डाई-पेंटेरीथ्रिटोल से अलग है। डाई-पेंटेरीथ्रिटोल को प्रस्तावित जांच के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसकी कीमत विचाराधीन उत्पाद की कीमत से बहुत अधिक है, लगभग 20 मी. टन प्रति वर्ष की सीमा तक उसकी सीमित माँग है और वह आई टी सी वर्गीकरण 2905.42.10 के अंतर्गत आता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यद्यपि 2905.42.10 वर्गीकरण डाई-पेंटेरीथ्रिटोल के लिए है तथापि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस वर्गीकरण के अंतर्गत सूचित आयात मुख्यतः पेंटेरीथ्रिटोल के आयात हैं।

2. घरेलू उद्योग की स्थिति

यह याचिका मै0 कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के तीन उत्पादक हैं। एशियन पेंट्स एक उत्पादक है और मुख्य रूप से उत्पाद का आबद्ध उपभोक्ता है। पेरसटॉर्प एजिस भारत में संबद्ध वस्तु का एक अन्य उत्पादक है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार पेरसटॉर्प एजिस ने अपने संबद्ध उत्पादक तथा स्वीडन स्थित निर्यातक से बड़ी मात्रा में आयात किए।

आवेदन प्राप्त करने के पश्चात् प्राधिकारी ने चीन जन. गण. तथा स्वीडन के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पर ज्ञात उत्पादकों के समर्थन अथवा विरोध को निर्धारित करने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के सभी ज्ञात निर्यातकों के विचार माँगे। भारतीय उत्पादन के विवरण, भारत में ज्ञात उत्पादकों के उत्तर तथा पेरसटॉर्प एजिस द्वारा स्वीडन स्थित अपने उत्पादक से किए गए आयातों के साक्ष्य की जांच करने के बाद प्राधिकारी विचार करते हैं कि पेरसटॉर्प एजिस को छोड़ा जाना आवश्यक है और वे नोट करते हैं कि पेरसटॉर्प एजिस के उत्पादन को छोड़ने के बाद और इस बात पर विचार किए बिना कि आबद्ध उत्पादन को छोड़ा गया है अथवा नहीं, याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।

उपर्युक्त की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह निर्धारण करते हैं कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु का एक प्रमुख उत्पादक है जिसका उत्पादन भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है और इसलिए याचिकाकर्ता नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और वह नियमावली के नियम 5(3)(क) के अनुसार याचिका दायर करने के मानदण्डों को पूरा करता है।

3. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य और स्वीडन (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) हैं।

4. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तुओं के समान वस्तु है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई विशेष अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वे दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता

द्वारा उत्पादित वस्तु को उपरोक्त नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

5. सामान्य मूल्य

स्वीडन में घरेलू कीमत, समान वस्तु की कीमत जब स्वीडन से उसका निर्यात अन्य देशों को किया गया और बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक लागतों एवं लाभ को जोड़ने के बाद उत्पादन लागत के अनुमान पर विचार करके घरेलू उद्योग ने स्वीडन में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा किया है।

चीन जन. गण. के मामले में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 एवं 8 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. और स्वीडन में संबद्ध वस्तु के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

6. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ता ने अद्यतन उपलब्ध अवधि के लिए डी जी सी आई एंड एस द्वारा जारी किए आयात आंकड़ों के आधार पर स्वीडन के मामले में निर्यात कीमत का दावा किया है और आई बी आई एस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (सूचना प्रणाली) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और सामग्री की निकासी से संबंधित प्रविष्टियों के वास्तविक बिल से उसे पूरा किया है। चीन के मामले में याचिकाकर्ता ने चीनी सीमाशुल्क द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया है, हालाँकि याचिकाकर्ता ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार निर्यात कीमत भी प्रस्तुत की है और उसे आई बी आई एस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के साथ पूरा किया है। कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा तथा निर्यात के देश में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन प्रहस्तन और पत्तन प्रभार के लिए, जहाँ कहीं भी लागू हो, समायोजन का दावा किया गया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

7. पाटन मार्जिन

प्रथम दृष्ट्या इस बात के साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में सम्बद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या इस बात का संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा सम्बद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

8. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ता ने घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित विभिन्न मानदंडों से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है। संबद्ध देशों से आयातों की सापेक्ष मात्रा में वृद्धि, कुल आयातों में संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि, भारत में उत्पादन तथा उपभोग की तुलना में आयातों में वृद्धि

बिक्री मात्राओं, बिक्री कीमतों, बाजार हिस्से में अत्यधिक गिरावट, लाभ, नकद प्रवाह, निवेश पर आय में अत्यधिक क्षरण, अत्यधिक कीमत कटौती एवं कम कीमत पर बिक्री जैसे मानदंडों से समग्र तथा संचयी रूप से प्रथम दृष्ट्या यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है। याचिकाकर्ता ने वास्तविक क्षति के खतरे का भी आरोप लगाया है।

9. पाटनरोधी जांच का आरंभ

उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं।

10. जांच की अवधि

वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2003 से 30 सितम्बर, 2004 तक (12 महीनों) की है।

11. सूचना देना

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से उनकी सरकारों, ज्ञात संबद्ध आयातकों और उपयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी),
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार,
कमरा सं०- 243, उद्योग भवन,
नई दिल्ली- 110011

को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचाराधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को, जो पाटन, क्षति एवं कारणात्मकता से संबंधित जांच के संगत सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं, भी अवसर प्रदान किया जा रहा है। अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है।

12. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर सूचना देनी होगी। यह नोट कर लिया जाए कि निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

13 सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

क्रिस्टी एल. फेर्नान्डेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2005

Subject : Initiation of Anti-dumping Investigations concerning import of Pentaerythritol originating in or exported from China PR and Sweden.

No. 14/16/2004-DGAD. M/s Kanoria Chemicals and Industries Limited has filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of Pentaerythritol originating in or exported from China and Sweden and has requested for initiation of anti-dumping investigations for levy of anti-dumping duties.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present case is Pentaerythritol, an organic compound (also referred to as subject goods hereinafter). The subject goods are classified within Customs subheading 29.05.42 and Indian Trade Classification based on Harmonized System. Investigations are being initiated with respect to product under consideration irrespective of the classification under which they are being imported. Customs classifications are indicative only and in no way binding on the scope of these investigations.

Petitioner has stated that Pentaerythritol can be of technical grade and nitration grade. Both grades are included within the scope of the product under consideration and proposed investigations.

Petitioner has stated that Pentaerythritol is different from Di- Pentaerythritol. Di-Pentaerythritol is not included within the scope of the proposed investigations, is a product priced significantly higher than product under consideration, has limited demand to the extent of approx. 20 MT per annum and falls under ITC classification 2905.42.10. According to the petitioner, even though 2905.42.10 classification is meant for di-pentaerythritol, petitioner has alleged that imports reported under this classification is largely imports of pentaerythritol.

297-52/2005-2

2. DOMESTIC INDUSTRY STANDING

The petition has been filed by M/s Kanoria Chemicals and Industries Limited. Petitioner claimed that there are three producers of the product under consideration in India. Asian Paints is a producer and largely captive consumer of the product. Perstorp Ageis is another producer of the subject goods in India. As per data presented by the petitioner, significant proportion of the imports were made by Perstorp Ageis from its affiliated producer and exporter in Sweden.

After receipt of the application, the Authority called for opinion of all the known producers of the subject goods in India to determine their support or opposition to the application filed by the petitioner for imposition of Anti dumping duty on imports originating in or exported from China PR and Sweden. After examining the details of Indian production, responses from the known producers in India, and evidence of imports made by Perstorp Ageis from its related producer in Sweden, the Authority considers that Perstorp Ageis is required to be excluded and notes that the production of the petitioner constitutes a major proportion of the Indian production, after excluding Perstorp Ageis production and regardless of whether or not captive production is excluded.

The Authority after examining the above, determines that the petitioner is a major producer of the subject goods in India accounting for a major proportion of the production of the subject goods in India and therefore the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of the rule 2(b) read with 2(d) and it satisfies the criteria of standing to file the petition in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra.

3. COUNTRIES INVOLVED

The countries involved in the present investigation are the People's Republic of China and Sweden (hereinafter also referred to as subject countries).

4. LIKE GOODS

The petitioner has claimed that goods produced by it are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. There is no significant difference in the subject goods produced by the petitioner and those exported from subject countries. Petitioner claims that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of present investigation, the goods produced by the petitioner are being treated as Like Articles of the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules, supra.

5. NORMAL VALUE

The Petitioner has claimed the normal value of the subject goods in Sweden considering domestic price in Sweden, price of the like article when exported from Sweden to other

countries and estimates of cost of production, after addition for selling, general, administrative costs and profit.

In case of China PR, the petitioner has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Anti Dumping Rules. Petitioner has provided evidence of normal value on this basis.

The authority notes that there is sufficient evidence of the normal value claimed for the subject goods in China PR and Sweden.

6. EXPORT PRICE

Petitioner has claimed the export price in case of Sweden based on the import data released by DGCI&S for the latest available period and has supplemented the same with the data provided by the IBIS (International Business Information System) and actual bill of entries relating to clearance of material. In case of China, petitioner has claimed export price based on the data released by the China Customs, even though petitioner has also provided export price as per the latest data released by the DGCI&S, supplemented with the data provided by IBIS. Adjustments have been claimed, wherever applicable, on account of ocean freight, marine insurance, and inland transportation in the country of exports, port handling and port charges to arrive at the export price at ex-factory level. There is sufficient evidence of the export price of the subject goods from the subject countries.

7. DUMPING MARGIN

There is, prima facie, evidence that the Normal Value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

8. INJURY AND CAUSAL LINK

Petitioner has furnished information on various parameters relating to injury to the domestic industry. Parameters such as increase in the absolute volume of imports from the subject countries, increase in the market share of imports from the subject countries in total imports, increase in imports in relation to production and consumption in India, decline in the import prices from the subject countries, significant decline in sales volumes, selling prices, market share, significant deterioration in profits, cash flow and return on investment, significant price undercutting and underselling, prima facie, indicate collectively and cumulatively that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of subject goods from subject countries. Petitioner has made allegation of threat of material injury also.

9. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

10. PERIOD OF INVESTIGATION

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st Oct., 2003 to 30th Sept., 2004 (12 months).

11. SUBMISSION OF INFORMATION

The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority, Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce, Government of India, Room No. 243, Udyog Bhavan, New Delhi – 1100 11.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is providing opportunity to the industrial users of the article under investigation also, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

12. TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

13. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence/application submitted by other interested parties. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority